जलवायु परिवर्तन– संसदीय प्रयासों के प्रभाव, चुनौतियां एवं उपलबधियां

हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व एवं परिस्थितियां उपस्थित हैं। विज्ञान एवं तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बनाया है और इस कारण हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास कर पाये है। परन्तु विकास की इस अभिलाषा में पर्यावरण की अनदेखी हुई है एवं प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन किया गया है। इससे पर्यावरणीय तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव हुआ है और हम जलवायु परिवर्तन के जाल में फंस रहे हैं।

नासा के अनुसार जुलाई 2019 का महीना पृथ्वी पर रिकार्ड किया गया सबसे गर्म महीना था। इस रिकार्ड गर्मी के कारण उत्तर ध्रुवीय एवं दक्षिण ध्रुवीय समुद्र की बर्फ का क्षेत्रफल ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर तक कम हो गया। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए विश्व समुदाय, जिसमे संसदे भी समिलित हैं, द्वारा कई पहल की गयी हैं।

यू0एन0एफ0सी0सी0 तथा उसके अन्तर्गत विभिन्न सम्मेलनों में उठाए गए पैरिस समझौते आदि कदमों से विश्व का ध्यान इस बात पर गया है कि इस भीषण चुनौती से निपटने के लिए सभी देशों को मिल कर विभिन्न प्रयासों में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी क्रम में वर्ष 2018 में जलवायु परिवर्तन के सी0ओ0पी024 सम्मेलन में सभी पक्षों ने पेरिस समझौते को क्रियान्वित करने के नियमों पर सहमति बनाई कि किस प्रकार विभिन्न सरकारें अपने अपने उत्सर्जन कम करने संबंधी प्रयासों का मापन और प्रतिवेदन करेंगी। पैरिस समझौते की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस वर्ष भी चिली के सानटियागो में होने वाले सी0ओ0पी025 सम्मेलन मे सभी देश मिल कर समझौते के सफल क्रियान्वयन के लिए कारगर कदमों पर विचार करेंगे।

भारत की संसद द्वारा भी जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मुख्य पहल की गयी हैं। हमने देश के विकास के एजेन्डा को सतत विकास लक्ष्यों के एजेन्डा साथ मिला दिया है। हमने जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए नीति निर्माण, जन जागरूकता, संवेदीकरण तथा क्रियान्वयन के लिए कई मंच स्थापित किये हैं।

लोकसभा द्वारा अध्यक्षीय शोध कदम नामक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसके अर्न्तगत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का विषय विशेषज्ञों की सहभागिता से विभिन्न कार्यशालाओं, सेमिनार तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से इस विषय के संबंध में संवेदीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत की संसद समिति प्रणाली के माध्यम से भी देश का ध्यान जलवायु परिवर्तन संबंधी विभिन्न पहलुओं की ओर केन्द्रित करने के लिए प्रभावी रूप से योगदान दे रही है।

हमारे यहां विज्ञान एवं तकनीकि तथा वन एवं पर्यावरण विभागों से संबन्धित स्थाई समितियां है जो जलवायु परिवर्तन के संबन्ध में सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है और इन प्रयासों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाती है।

भारत ने पैरिस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं और देश अपने विकास का एजेडा को ध्यान में रहते हुए जलवायु परिवर्तन का सामना करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हमारी प्राथमिकता देश से गरीबी का उन्मूलन करना तथा सभी नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराना है ता वहीं हम स्वच्छ उर्जा तकनीक तथा वित्तीय संसाधन के प्रयोग से विकास के कम कार्बन उत्सर्जन वाले रास्ते पर चलने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

देश में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही है जो राज्य कार्य योजना के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में कार्य करती है। हमने उन राज्यों एवं क्षेत्रों के लिए, जो जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव से अधिक प्रभावित हो सकते हैं, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन फंड स्थापित किया है ताकि इन क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल स्वयं को ढालने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त हानिकारक तत्वों के उत्सर्जन को कम करने तथा ईंधन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इलैक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक अधिक से अधिक ईलक्ट्रिक वाहन चलाने का उददेश्य देश ने रखा है।

हमारे प्रधानमंत्री स्वयं जलवायु परिवर्तन संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में सक्रियता से प्रतिभाग करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद राष्ट्रीय कार्य योजना का समन्वय करती है तथा इस खतरे से निपटने के लिए विभिन्न समयपूर्व उपायों के संबंध में सरकार को परामर्श देती है। हम आजकल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एकल प्रयोग प्लास्टिक का पूर्ण रूप से प्रयोग रोकने पर ध्यान केद्रित कर रहे हैं, जो विश्व के प्लास्टिक प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है।

हमारे राज्य उत्तराखण्ड में भी पर्यावरण संरक्षण के संबंध में विभिन्न पहल की गयी हैं। हमारी विधान सभा में अध्यक्षीय शोध कदम–उत्तराखण्ड विधान सभा प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत हमने पर्यावरण जागरूकता सेमिनार तथा अन्य गतिविधियां की। राज्य में हमें सी0पी0ए0 जोन–01 की बैठक आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जो देश में किसी भी जोन की पहली बैठक थी। उस बैठक में हमने हिमालय में स्वस्थ जल तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के राजधानी नगर से नहने

वाली रिस्पना नदी के वृहत स्तर पर पौधारोपण तथा अन्य उपायों के माध्यम से पुनरुद्धार के लिए किये जा रहे प्रयासों से अवगत कराया।

निःसंदेह जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं परन्तु कुछ एसे चुनौतीपूर्ण विषय हैं जिनका समाधान निकालना जलवायु परिवर्तन पर प्रभावी कार्य के लिए आवश्यक है। एक मुख्य विषय यह है कि विश्व के अविकसित देशों को आशंका है कि उत्सर्जन कम करने के आन्दोलनों से उनका विकास प्रभावित होगा। जलवायु परिवर्तन के समाधान के साथ साथ विश्व में गरीबी उनमूलन एवं विकास पर भी कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इन विषयों के समाधान के लिए सभी सम्बन्धित पक्षों के बीच खुला एवं विस्तृत विचार विमर्श किये जाने की आवश्यकता है।

हमारी नीति यह होनी चाहिए कि समाज पर जलवायु परिवर्तन के खतरे को न्यूनतम किया जा सके। नयी औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरण अनुकुलित शैली मे विकसित किये जाने की आवश्यकता है। हमें नीति निर्माण में वानिकी तथा पौधारोपण अभियान को प्राथमिकता देनी चाहिए तो दूसरी ओर जनसंख्या नियत्रण से भी आवासीय आवश्यकता के लिए वनों का कटाव रोका जा सकता है।

हमे यह समझने की आवश्यकता है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या एक जटिल विषय है जिसमें विकास, जनसंख्या, संसाधन, पर्यावरण तथा आर्थिक न्याय का ताना बाना बुना है। समस्या के समाधान की कोई भी वैश्विक रणनीति बनाने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विश्व के सभी देशों, चाहें वे गरीब हों या अमीर, के मध्य सहयोग की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे कंधों पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आईये, इस दिशा में मिलकर प्रयास करें ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर पृथ्वी और एक बेहतर वातावरण बना सकें।